नाबार्ड का सर्वे • 1 लाख परिवारों का आर्थिक विश्लेषण

5 साल में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय 57.5% बढ़ी

संजीब मुखर्जी | नई दिल्ली

हमारे गांवों में पांच साल में मासिक आय 57.5% बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों की औसत घरेलू मासिक आय 2016-17 में 8,059 रु. थी, जो 2021-22 में 12,698 रु./माह हो गई। हालांकि, इस दौरान बकाया कर्ज 47.4% से बढ़कर 52% पर चला गया। बुधवार को जारी नाबार्ड के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इनक्लुजन सर्वे (एनएएफआईएस) 2021-22 में ये बातें कही गई हैं।

सर्वे के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की मासिक आय सालाना 9.5% की दर से बढ़ रही है, जो देश की नामिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 9% से ज्यादा है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों का मासिक खर्च 2016-17 के 6,646 रु. से बढ़कर 2021-22 में 11,262 रु./माह हो गया। - शेष पेज 10 पर

गांवों में साहूकारों से कर्ज लेने वाले घटे

- सर्वे के अनुसार, ग्रामीण परिवारों की वित्तीय बचत 2021-22 के दौरान 13,209 रु./माह हो गई, जो 2016-17 में 9,104 रु./माह थी।
- सर्वे में शामिल एक लाख लोगों में 66% लोगों के पास कुछ न कुछ बचत थी, 2016-17 में ऐसे परिवारों का आंकड़ा 50.6% पर ही था।
- वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या 2016-17 में 60.5% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 75% हो गई। मायने ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट साहूकारों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है। 23.5% परिवार ऐसे हैं, जिनके कम से कम एक सदस्य को पेंशन मिलती है, 2016-17 में ऐसे 18.9% परिवार ही थे।

5 साल में ग्रामीण ...

इस सर्वे को एक लाख ग्रामीण परिवारों से प्राप्त आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें 56.7% कृषक परिवार और बाकी गैर कृषक परिवारों से थे।

खान-पान पर होने वाला खर्च 5 साल में 4% घटा

- सर्वे में उन परिवारों को कृषक परिवार कहा गया, जो कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से 6,500 रु./माह आय अर्जित करते हैं। साथ ही 2021-22 में परिवार का कम से कम एक सदस्य किसानी में लगा है।
- शुद्ध आमदनी की गणना करते समय सभी मदों से अर्जित धन को जोड़कर उसमें वह राशि घटा दी गई, जो आय के लिए खर्च होती है।
- अर्जित आय से खान-पान में होने वाले खर्च का हिस्सा घटा है। यह पांच साल में 51% से घटकर 47% रह गया है। प्रति परिवार भू स्वामित्व 1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर ही रह गया है।
- गांवों में कृषि से होने वाली आय की हिस्सेदारी 35% से घटकर 20% पर आ गई है। वेतन और मजदूरी से आय की हिस्सेदारी बढ़ी है।